समय एम्स को कार्यरूप में शुरू करने के लिए वर्ष 2009 तक का समय रखा गया था। बिहार में कोई भी उत्कृष्ट अस्पताल नहीं है। इस कारण दिल्ली के एम्स अस्पताल में 60 परसेंट बिहार के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। बिहार में गरीबी है, फटेहाली है इस कारण कई लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आ भी नहीं पाते हैं। बिहार के लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बिहार में एम्स अस्पताल खुल जाएगा, तो न सिर्फ बिहार के लोगों को, बल्कि बिहार से सटे नेपाल, असम तथा आसपास के इलाकों के लोग भी लाभांवित हो सकेंगे। कई बार हमने सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है। आश्वासन मिलने के बावजूद भी आज तक इस बारे में तेज रफ्तार से काम नहीं हो रहा है। पता नहीं यह काम कितने वर्षों में पूरा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। अब आप समाप्त कीजिए। You are now repeating the same thing.

श्री राम कृपाल यादव: कई लोगों के पास दिल्ली इलाज के लिए आने के लिए भाड़े के पैसे नहीं होते हैं। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस बारे में उत्तर दें कि कब से काम शुरू होगा और कब काम खत्म होगा। बिहार जैसे गरीब देश में लोगों को इलाज कराने में बहुत परेशानी होती है।

SHRI KHARABELA SWAIN: Sir, hon. Minister is here. He should reply not only to the hon. Member's question but other questions also. I have asked a number of questions.

MR. DEPUTY SPEAKER: I cannot compel the Minister to reply.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): Sir, under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana the Government of India intends to start six new AIIMS like institutions in States like Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttarakhand and Chhattisgarh. The CCA had given approval only in 2006. Since then we have been going through a lot of process. One tender was un-responsive. Another tender was a single bidder. We had to go through the project management consultants. In all we have to go through a lot of process and there was a delay. I accept the responsibility for delay on part of my Ministry. Nevertheless, I had again asked them to quicken the process. Finally, I could say that the construction work has started in five out of six AIIMS like institutions, including Bihar, Orissa and Rajasthan. Except Bhopal, work at other five sites has already begun and at Bhopal the work will start in the beginning of November.

I categorically assure that the work has started and the entire construction work will be over in another two-and-a-half to three years and it will be fully functional. Not only that, we also want to upgrade some more institutions in Northern part of the country. We have added some more institutions, which again after getting the approval we will inform the hon. House.

SHRI J.M. AARON RASHID: Sir, since the hon. Minister belongs to Tamil Nadu, he should see to it that Tamil Nadu also has such an institution.

SHRI P.S. GADHAVI (Kutch): Sir, I would like to raise a very important issue concerning my constituency regarding the development of Jakhau Fishery Harbour Project....*(Interruptions)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को तमाम राज्य के लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनको इन्होंने उपहार देने का काम किया है। स्वाईं जी आप भी मंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैं कई बार मंत्री जी को धन्यवाद दे चुका हूं।

SHRI P.S. GADHAVI: Sir, I would like to raise an important issue concerning my constituency regarding the development of Jakhau Fishery Harbour Project. Jhakau port is just near Pakistan on the Western border of the country.

The Government of India had accorded administrative approval to Jakhau Fishery Harbour under hundred per cent Centrally sponsored scheme amounting to Rs. 11.43 crore in May 1993. This harbour was designed in such a way that it could accommodate vessels of Coast Guard, Navy for national security purposes.

However, the construction work of the project got delayed substantially because of the Government of India's pre-condition of obtaining environment clearance before the commencement of construction work resulting in cost escalations twice. The revised cost estimates of Rs. 34.84 crore were submitted by the Government of Gujarat to the Government of India in August 2007. Thus, the approval of the Government of India towards the difference amount of Rs. 23.41 crore is awaited since August 2007.

[Shri P.S. Gadhavi]

It is pertinent to mention here that Jakhau is strategically located and has national security importance. The Government of India has accorded administrative approval on this project under 100 per cent CSS, as a special case.

I, therefore, urge upon the Central Government to sanction and release the difference amount of Rs. 23.41 crore incurred by the State Government on the project, as immediately as possible.

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मुझे इस सीट से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इस सीट से बोलने की इजाजत दी जाती है।

डॉ. करण सिंह यादव: महोदय, इन दिनों में राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर में सरसों और गेहूं की बुआई का सीजन शुरू है। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां के किसानों को डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है और इसकी बहुत कमी है। यहां से राजस्थान के लिए कोटा एलॉटमेंट कम है, कुछ ब्लैक मार्किट में चला जाता है जिसके कारण अलवर के किसान हरियाणा से कालाबाजारी से खरीदकर लाते हैं। इसकी गुणवत्ता बहुत कम है और किसान ठगा जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में विशेष तौर से अलवर जिले में डीएपी की मात्रा का कोटा बढ़ाया जाए और उचित व्यवस्था की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, मारवाड़ी हिन्दुस्तान की पश्चिमी बोली में राजस्थानी समूह की सबसे बड़ी बोली है। प्राय: मारवाड़ी को राजस्थानी के पर्याय के रूप में जाना जाता है लेकिन ये बोली मुख्यत: राजस्थान के मध्य एवं पश्चिमी भाग के बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में बोली जाती है। इस क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी समुदाय एक ऐसा व्यावसायिक समुदाय है जो दुनिया भर में फैला हुआ है और इनका अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है। अत: ये घर परिवार सामाजिक कार्यों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है इसके बोलने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ है। हिन्दी की तरह मारवाड़ी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसका व्याकरण भी हिन्दी जैसा ही है। इसके 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक शब्द हिन्दी जैसे ही हैं। मारवाड़ी का शिक्षा के माध्यम या सरकारी कामकाज में उपयोग नहीं होता है इसका कारोबार में उपयोग होता है। राजस्थानी समूह की अन्य बोलियों में हाडोती, मेवाढ़ी, ढूढारी, मेवाती, शेखावटी और बागड़ी आदि शामिल हैं। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि संविधान की आठवीं सूची में इस भाषा को शामिल किया जाए जिससे इसकी मान्यता और उपयोग बढ़ सके और राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिल सके।

डा. करण सिंह यादव: आप राजस्थान के टुकड़े क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

*...(Interruptions)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आपने राजस्थान की जो खाद की समस्या बताई है मैं तो आपके साथ एसोसिएट कर रहा हूं। लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, अगर मारवाड़ी मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। *...(व्यवधान)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing would go on record now.

*(Interruptions)** ...

SHRI P.C. THOMAS (Muvattupuzha): The waiver and the relief scheme to the farmers is a very good scheme which is going to help many farmers. But when the scheme was to be implemented, the Government framed guidelines and according to those guidelines many of the declared benefits which were to accrue to the farmers have been curtailed. I can quote one example. In the Budget declaration in the Lok Sabha it was mentioned that all loans before 31.03.07 will be waived in case of all those eligible ones. But when it came to implementation, clause 4 of the guidelines stipulated that all long term loans before 01.03.97 will be out of the scheme. That is totally against what had been declared in the Lok Sabha.

There is another one and that is for short-term loans it was said that all the loans would be waived. But when it came to the guidelines, clause 3 of the guidelines states that in case of short-term loans a limit is fixed and that is Rs. 1,00,000/-. Any loan above Rs. 1,00,000/- would

*Not recorded.